>

Title: Shortage of Chemical fertilizers in Uttar Pradesh.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): धन्यवाद सभापति महोदय,उर्वरक के बिना खेती की बात बेइमानी है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ की फसल हेतु नौ-दस फरवरी 2011 को जोनल कॉनफ्रेन्स में अंतिम निर्णय किया। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख टन यूरिया 10.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 5.25 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 1.50 लाख मीट्रिक टन एमओपी की आपूर्ति किए जाने की सहमति की गई। जून, 2011 तक मांग के सापेक्ष यूरिया 80 प्रतिशत, डीएपी 30 प्रतिशत, एनपीके 78 प्रतिशत और पोटाश 27 प्रतिशत की आपूर्ति हो पाई है। इस प्रकार जून तक मांग के सापेक्ष 32 प्रतिशत की आपूर्ति की कमी रह गई। इस दिशा में भारत सरकार की सहमति के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से मांग की कि आप यह कमी पूरी करें। मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध न होने की दिशा में कृषकों को व्यापक असंतोष हो रहा है। इतना ही नहीं, 278 रुपये प्रति बोरी डीएपी में बढ़ा। जिसने भारत सरकार के स्तर पर वर्ष 2010-11 के सापेक्ष यूरिया में 18.88 पैसे की वृद्धि, डीएपी में 109 रुपये की वृद्धि और एनपीके में 143 रुपये की वृद्धि हुई जो किसानों के हित में नहीं है।...(व्यवधान)

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मूल्य वृद्धि घटाई जाए और खाद की जो मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने की, वह उसे दी जाए।